सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (MDGs)

1. अतिशय गरीबी(Extreme poverty) व भूखमरी उन्मूलन
2. सर्वव्यापक (universal)प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति
3. लैंगिक समानता व महिला सशक्तीकरण
4. शिशु मृत्यु दर कम करना
5. मातृक स्वास्थ्य में सुधार
6. एचआइवी/मलेरिया व अन्य बीमारियों से सामना
7. पर्यावरणीय निरन्तरता सुनिश्चित करना
8. समृद्धि एवं विकास के लिए विश्वस्तरीय साझेदारी

DPMUs का पता

1-DPMU - Hazaribagh
District Planning Office
DRDA Building, Collectorate Campus
Hazaribagh – 825 301, Jharkhand
Tel : 06546 - 265347
Fax : 06546 - 264808
E-mail : hzh.dpmu@gmail.com

2-DPMU - Gumla
District Planning Office, Vikas Bhawan
Collectorate Compound
Gumla – 835 207, Jharkhand
Tel : 06524 - 224732
Fax : 06524 - 223084
E-mail : gml.dpmu@gmail.com

3-DPMU - Pakur
District Planning Office
District Collectorate
Pakur – 816 107
Jharkhand
Tel : 06435 – 221155 / 222173
Fax : 06435 - 222255
E-mail : pkr.dpmu@gmail.com

4-DPMU - Palamu
District Planning Office
District Collectorate
Medini Nagar
Palamu – 822 101, Jharkhand
Tel : 06562 - 230859
Fax : 06552 - 224077
E-mail : pmu.dpmu@gmail.com

5-DPMU – West Singhbhum
District Planning Office, Room No. – 08
Vikas Bhawan, Chaibasa – 833 201
West Singhbhum, Jharkhand
Tel : 06582 - 256620
Fax : 06582 - 256442
E-mail : ws.dpmu@gmail.com

Address of State Nodal Office

GoI – UN Joint programme on Convergence

Department of Planning & Development
Ground Floor, Nepal House , Doranda,
Ranchi - 834 002, Jharkhand
Tel / Fax : 0651 - 2490296
E-mail : jpc.jkd@gmail.com

भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र द्वारा झारखण्ड राज्य में अभिसरण (Convergence) पर संयुक्त कार्यक्रम की संक्षिप्त विवरणी

कार्यक्रम की पृष्ठभूमि

झारखण्ड में विगत कुछ वर्षों में निरंतर विकास हुआ है, जिसकी परिणति घटती गरीबी के परिप्रेक्ष्य में (झारखण्ड में 34.8% BPL- 2004 - 05) स्पष्ट दृष्टिगोचर है ; तथापि झारखण्ड के सामने सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (MDGs) को ससमय हासिल करने में कई चुनौतियाँ हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकेन्द्रीकरण तथा परिणामजन्य योजनाओं पर बल दिया गया है, ताकि विकास योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के साथ–साथ समेकित वृद्धि लाई जा सके। विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अभिसरण की कमी, एक बड़ी बाधा साबित हुई है, जिस कारण निधि का पर्याप्त तथा तथ्यपरक उपयोग नहीं हो पाता है। झारखण्ड राज्य के पाँच जिलो में प्रारम्भिक चरण में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है।

उद्देश्य एवं संदर्भ

अभिसरण पर आधारित उक्त संयुक्त कार्यक्रम का उद्देश्य 7 राज्यों के 5 पिछड़े जिलों में जीविकोपार्जन, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्रों में चलाये जा रहे कार्यक्रमों में तीव्रता तथा अच्छे परिणाम लाना है। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अवरोधों की पहचान करके, कार्यक्रमों में लगाये जा रहे प्रयासों एवं बलों में समन्वय तथा अभिसरण के द्वारा विद्यमान सरकारी संसाधनों को तकनीकि सहायता उपलब्ध कराकर MDGs तथा 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य को पाने का उद्देश्य रखा गया है।

Flagship कार्यक्रमों में कर्णांकित राशि का लगभग 50% ही व्यय हो पाता है साथ ही संसाधनों का महत्तम उपयोग भी नहीं हो पाता है, जो जिलों के मानव विकास मानदण्डों से स्पष्टतः परिलक्षित होता है।

कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं रूपरेखा :-

झारखण्ड के पाकुड़, पलामू, पश्चिमी सिहंभूम, गुमला तथा हजारीबाग में यह कार्यक्रम तकनीकि सहायता मुहैया करायेगी ताकि **MDGs** तथा 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य पाये जा सकें। इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध राशी को राज्य एवं जिला स्तर की आधारभूत संरचना, मानव संसाधन, कार्यालय सहायता, प्रशिक्षण एवं **GIS** जैसी तकनीकि व्यवस्थाओं पर खर्च किया जायेगा।

उक्त कार्यक्रम में ; **UNDP** (सहायता–जिला स्तरीय क्षमता विकास कार्यक्रम) :**UNICEF** (सहायता–जिला उत्प्रेरकों) तथा **UNFPA** (सहायता–आंकड़ों के प्रबंधन एवं उपयोग) मुख्य बाह्य सहयोगी ऐजेन्सियाँ हैं, जो योजना आयोग तथा झारखण्ड सरकार के सहयोग से कार्य करेंगी।

कार्यक्रम के दस्तावेजों एवं त्रिपक्षीय **MoU** के आधार पर सर्वप्रथम कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विद्यमान बाधाओं की पहचान कर उनका विश्लेषण करना है ताकि जिला के उन खण्डों/उप खण्डों को चिन्हित कर वहाँ **Flagship** कार्यक्रमों को दृढ़ता एवं व्यवस्थित तरीके से लागू किया जा सके। कार्यक्रमों में सम्मिलित सभी संसाधनों का उपयोग, अभिसरण एवं समन्वय के साथ एक दिशा में महत्तम परिणाम हेतु प्रबंध करना तथा उसपर आधारित जिलावार योजना बनाना, इस कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियाँ हैं।

इस कार्यक्रम के मुख्य आयाम अधोवर्णित हैं :-

- जिला योजना समिति **(DPC)** द्वारा जिला स्तर पर भागीदारी आधारित योजना तैयार करना तथा उसमें सुधार करना।
- जिला स्तर पर बजट एवं संसाधन प्रबंधन एवं समझ का विकास।
- **Flagship** कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आनेवाली रूकावटों का मूल्यांकन तथा उसके उपाय।
- कार्यक्रमों, खर्चों, परिणामों का निरंतरण अनुश्रवण।

झारखण्ड में योजना एवं विकास विभाग द्वारा चयनित पाँच जिलों क्रमशः पलामू, गुमला, प० सिंहभूम, हजारीबाग एवं पाकुड़ में कार्यक्रम प्राथमिक चरण में तीन वर्षों (2009–12) के लिए लागू किया गया है। झारखण्ड सरकार के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के तकनीकि विशेषज्ञ, राज्य एवं जिला स्तर पर छोटे–छोटे समूहों में कार्य करते हैं। राज्य स्तर पर योजना एवं विकास विभागाध्यक्ष तथा जिला स्तर पर उपायुक्त के सीधे निरीक्षण में उक्त कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमिटि गठित है। विकास आयुक्त, झारखण्ड इसके सहअध्यक्ष तथा प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड इसके सदस्य – सचिव हैं। उपसचिव, योजना एवं विकास विभाग, उक्त कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी हैं, जिनकी देखरेख में वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबंधन प्रावधित हैं। राज्यस्तरीय समन्वय समिति में सभी संबंधित विभागों के सचिव/प्रधान सचिव के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के राज्य प्रतिनिधि भी शामिल हैं, जो प्रतिवर्ष 3–4 बार कार्य योजना से संबंधित बैठक द्वारा उक्त कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे।

अपेक्षित परिणाम :-

- सहभागिता आधारित जिला नियोजन में सुधार।
- परिस्थिति विश्लेषण व दृष्टि–क्षमता में सुधार कर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को चिन्हित करना तथा अभिसरण आधारित कार्य बिन्दु तैयार करना।
- सांख्यिकी आंकड़ों के सही व विस्तृत उपयोग हेतु प्रशिक्षण का आयोजन।
- जिला के बजट निर्माण प्रक्रिया में सहयोग, संसाधनों की पहचान तथा उनका उपयोग, बजटीय प्रावधान तथा निधि–प्रवाह।
- कार्यक्रम कार्यान्वयन में उत्पन्न बाधाओं/समस्याओं की पहचान तथा उनका विश्लेषण।
- समस्त कार्यक्रम गतिविधियों का बहुस्तरीय अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन प्रकाशन।

झारखण्ड में कार्यक्रम की अवस्थिति :-

- मार्च, 2009 में झारखण्ड सरकार द्वारा संयुक्त कार्यक्रम का अनुमोदन।
- त्रिपक्षीय (झारखण्ड सरकार, संयुक्त राष्ट्र के resident समन्वयक तथा योजना आयोग) MoU पर हस्ताक्षर।
- पाँचो चयनित जिलों में District Launch Workshop का आयोजन।
- जिला योजना पदाधिकारियों सहित अन्य पदाधिकारियों/ कर्मियों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण।
- संबंधित विभागों की राज्यस्तरीय अभिसरण बैठक का आयोजन।
- District Planning and Monitoring Units (DPMUs) जिसमें जिला स्तरीय सरकारी पदाधिकारी DPO, DSO, DIO, तथा UN के DF's, DSO's शामिल हैं, कार्यरत हैं।
- पाँचों जिलों में Flagship कार्यक्रमों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण का कार्य प्रारम्भ।
- विविध प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रमों जैसे मानेश्वर (हरियाणा) में विकेन्द्रीकृत जिला योजना, जमशेदपुर मे DevInfo Software, बंगलुरू में डाटा प्रशिक्षण, कोलान (केरल) में विकेन्द्रीकृत आयोजना गुड़गाँव में क्षमतावर्धन, जयपुर में Audit Clinic, भोपाल में UNVs का क्षमतावर्धन, कोलकता में ToT on Convergence आदि का आयोजन।
- द्वितीय राज्यस्तरीय स्टीयरिंग कमिटि की बैठक का आयोजन तथा AWP 2010 की स्वीकृति।
- द्वितीय राज्यस्तरीय Convergence कमिटि की बैठक का आयोजन।
- जिला मानव विकास प्रतिवेदन (DHDR) निर्माण हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन तथा उक्त कार्यार्थ एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ।
- राज्यस्तरीय MDG अवस्थिति प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार।
- जिला प्रोफाइल तैयार ।
- जिलों में प्रमुख Flagship कार्यक्रमों के Budget Tracking की प्रक्रिया प्रारम्भ।
- प्रत्येक जिला में एक आदर्श पंचायत का चिह्नीकरण तथा कार्यक्रम गतिविधियाँ प्रारम्भ।